SOCIAL & POLITICAL RESEARCH FOUNDATION
Dialogues For Better Democracy

वेबिनार रिपोर्ट

कोविड 19 के समय में स्ट्रीट फ़ूड के प्रश्न और खाद्य सुरक्षा पर जाँच

लच्छा पराठा
चिकन पकौड़ा

SPRF के विषय में

सोशल और पोलिटिकल रिसर्च फ़ाउंडेशन का काम साक्ष्य आधारित, निष्पक्ष और सुलभ पोलिसी रिसर्च को फ़ोकस में लाना है। एक युवा और सक्रिय विचार मंच होने के नाते हम रिसर्च, अपनी पहुँच और कार्यक्रमों द्वारा उस भारत के विषय में विमर्श करते हैं जहाँ पब्लिक पोलिसी तथ्यों के आधार पर सशक्त होती हैं ना कि विचारों से प्रभावित होती है। हमारे काम में टेक्नोलोजी और विशाल डेटा एनालिटिक्स द्वारा भारत के सतत परिवर्तनशील पोलिसी परिदृश्य को जानकारी देना और प्रभावित करना है। जो आवाज़ें हम प्रजातांत्रिक क्षेत्र में रखते या क्यूरेट करते हैं वो उस देश की अपेक्षाओं को प्रदर्शित करता है जहाँ कि आधी से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम की है।

परिचय

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू 'ज़ीरो हंगर' का उद्देश्य 2030 तक हर प्रकार की भूख और कुपोषण को मिटाना है। इसलिए UN मेंडेट के तारतम्य में हीं भारत ने भी सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देने, छोटे किसानों को समर्थन, सभी को भूमि, तकनीक और बाज़ार की उपलब्धता की दिशा में काम किया है। केंद्र सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत राशन का प्रावधान किया है, पर इस महामारी ने शहरी अमीर और शहरी निर्धन के बीच का फ़ासला और भोजन और पोषण की खाई को और बढ़ाया है।

स्ट्रीट फ़ूड, शहरी निर्धन और कम मज़दूरी वाले श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा के क़रीब लाता है। स्ट्रीट फ़ूड की व्यापक रेंज और आसान उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में निर्धनों की भोजन ज़रूरतों को बड़े स्तर पर पूरा करता है। इसके अलावा स्ट्रीट फ़ूड शहरी निर्धन के लिए रोज़गार का प्रमुख ज़रिया है। आमतौर पर खाना बनाना औरतों का काम माना जाता है इसलिए स्ट्रीट फ़ूड इंडस्ट्री को महिलाओं के आर्थिक उत्थान का शस्त्र बनाया जा सकता है।

SPRF ने अपने पहले वेबिनार के माध्यम से शहरी स्ट्रीट फ़ूड सेक्टर के साथ समग्र रूप से लग कर भारतीय खाद्य सुरक्षा में मौजूद दरारों की मरम्मत करने का प्रयास किया है। वेबिनार ने स्ट्रीट फ़ूड की etymology यानी शब्द व्युत्पत्ति, economy यानि अर्थव्यवस्था और उसकी sociology का गहन विश्लेषण किया और साथ साथ सामान्य जनजीवन की धारणा में स्ट्रीट फ़ूड खाद्य सुरक्षा के मामले में क्या जगह रखता है।

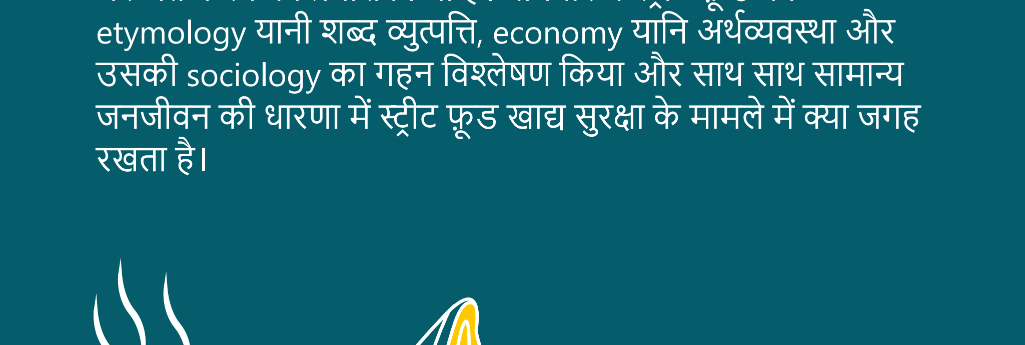

वक्ताओं के नज़रिए में

मिस पृथा सेन

Food Researcher I Development Consultant

मिस पृथा सेन एक जानी मानी फ़ूड हिस्टोरियन और डेवलपमेंट कंसलटेंट हैं। एक पाककला विशेषज्ञ और पत्रकार होने की वजह से ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों के लिए नियमित रूप से लेखन करती हैं।

मिस सेन इससे शुरुआत करती हैं कि जहाँ भी शहर होंगे वहाँ आपको स्ट्रीट फ़ूड वेंडर मिल जाएँगे। ये वेंडर ना सिर्फ़ आपको मनोरंजन की जगह उपलब्ध कराते हैं बल्कि उन ग्राहकों को सस्ता और सहजता से भोजन उपलब्ध कराते हैं जो यहाँ आते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट फ़ूड हमारे शहरों और सार्वजनिक स्थलों की विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो अप्रवासी शहरों के विस्तार की वजह से शहर आते हैं उनकी स्ट्रीट फ़ूड से ना सिर्फ़ भोजन की ज़रूरत पूरी होती है परंतु वो उनकी कमाई का ज़रिया भी बनता है।

अपने विमर्श के अंत में मिस सेन इस बात को प्रमुखता देती हैं कि ये सरकार और नीति निर्माताओं की ज़िम्मेदारी है कि वो इन वेंडर के अधिकार सुरक्षित करें। ख़ासकर कोविड 19 के समय में इंफ़्रास्ट्रकचर की कमी के प्रश्न पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। वो इस बात पर ज़ोर देतीं हैं कि सरकार को आधारभूत सुविधाएँ जैसे पानी, वेस्ट मेनेजमेंट, सफ़ाई, ख़ाना परोसने और बिज़नेस चलाने के लिए किफ़ायती पर्यावरण सहज या ईको फ्रेंडली सामान उपलब्ध कराना चाहिए।

मिस सेन ने वेंडरो के बीच नीतियों और स्कीम के बारे में जानकारी की कमी की भी बात की है। हालाँकि जानकारी के प्रसार का भी उत्तरदायित्व सरकार पर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँच सके।

मिस श्वेता शर्मा

Doctoral Researcher at University of Sheffield

मिस श्वेता शर्मा शेफ़ील्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टोरल रिसर्चर हैं और इससे पहले स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में असिसटेंट प्रोफ़ेसर थीं। इन्होंने दिल्ली, चेन्नई और विजयवाडा के स्ट्रीट वेण्डिंग के सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक विषय पर विस्तार में रिसर्च की है।

मिस शर्मा ने शहरी खाद्य सुरक्षा को बचाए रखने में स्ट्रीट फ़ूड वेंडर की अहम भूमिका को स्वीकारा है। इन्होंने इस भावना की पुष्टि की है कि स्ट्रीट फ़ूड निर्धन आबादी की पोषण ज़रूरत को कई विकल्पों के ज़रिए पूरा करता है। इसके साथ ये सेक्टर, अप्रवासियों को रोज़गार भी देता है।

मिस शर्मा ने इंफ़्रास्ट्रक्चर गेप, बेकार साफ़ सफ़ाई और इस सेक्टर में व्याप्त ख़राब प्रबंधन पर भी चर्चा की है। उन्होंने फिर ये भी बताया कि महामारी की वजह से ग्राहकों में स्ट्रीट फ़ूड ख़रीदने से परहेज़ हुआ जिससे कि स्ट्रीट फ़ूड अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह लॉकडाउन की वजह से गाँव की ओर पलायन ने स्ट्रीट वेंडर को भारी नुक़सान पहुँचाया है। सबसे बड़ी परेशानी जो हुई वो था ग्राहकों से सम्पर्क का टूटना जिसे वेंडरों ने इतने सालों में बनाया था।

मिस शर्मा अपनी स्टडी के आधार पर कई जानकारियों पर चर्चा करती हैं जिसमें स्ट्रीट फ़ूड सेक्टर में श्रम का जेंडर के आधार पर विभाजन भी शामिल है। ये उस पर भी प्रकाश डालती हैं कि किस तरह से इस सेक्टर में दो श्रेणी में महिलाएँ हैं। एक उन औरतो की श्रेणी है जो घर के ख़राब माली हालात और शारीरिक उत्पीड़न की वजह से इस सेक्टर में ज़बरदस्ती ढकेल दी जाती हैं। दूसरी वो औरतें हैं जो या तो अविवाहित हैं या विधवा, या तलाक़शुदा या फिर परित्यक्ता। ऐसी औरतों के निम्न शिक्षा स्तर, आर्थिक हालात, उनकी सामाजिक परिस्थिति, स्ट्रीट फ़ूड सेक्टर में उनकी पहुँच को आसान बनाती है।

मिस शर्मा ने ये भी देखा कि स्ट्रीट फ़ूड सेक्टर में काम करने के लिए शिक्षा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि उम्र। 20 वर्ष से कम आयु वाली युवतियाँ अपने माता पिता से मनुहार कर स्कूल जाती हैं और उसके बदले फ़ूड स्टाल के काम में हाथ बँटाती हैं। हालाँकि, पारिवारिक बिज़नेस में उनकी हिस्सेदारी नाम की ही होती है। हाल में भारत सरकार ने प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पी एम स्वनिधि) की शुरुआत की है।

जब मेज़बान ने स्कीम की प्रभावशीलता के मुद्दे पर उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ा ज़ोर देकर कहा कि जब तक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर को रेजिस्टर नहीं करती तब तक उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नहीं पहुँच सकतीं।

इस संदर्भ में उनका मानना है कि स्टेकहोल्डर की भागीदारी और सरकार को दिशा निर्देश सुझाने में टाउन वेण्डिंग कमिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

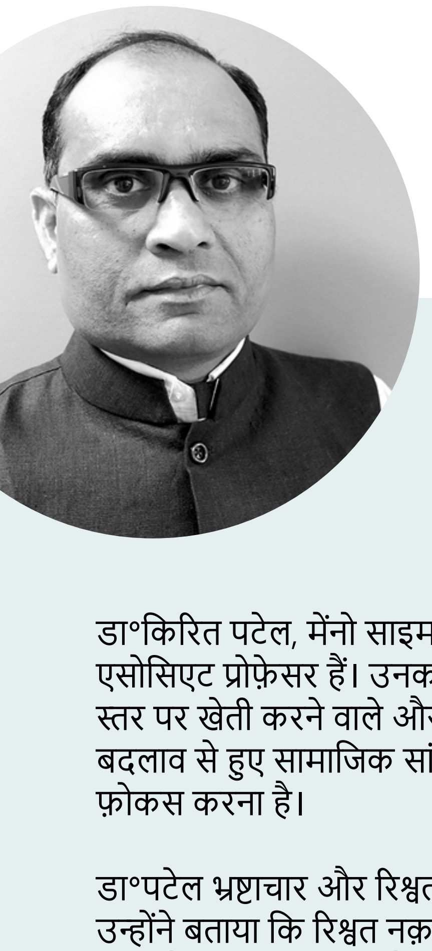

डा॰ किरित पटेल

Associate Professor at Menno Simons College, The University of Winnipeg

डा॰किरित पटेल, मेंनो साइमनस कॉलेज, यूनिवर्सिटी आफ विन्निपेग में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। उनका काम मुख्यतः ग्लोबल दक्षिण में छोटे स्तर पर खेती करने वाले और स्थानीय समुदायों पर पर्यावरणीय बदलाव से हुए सामाजिक सांस्कृतिक और एकोलोजिकल पहलू पर फ़ोकस करना है।

डा॰पटेल भ्रष्टाचार और रिश्वत के मुद्दे को बहुत गम्भीर मानते हैं। उन्होंने बताया कि रिश्वत नक़द और सामानों दोनों रूपों में मौजूद है। एक और मुख्य समस्या औरतों की एजेंसी का ना होना है। उन्होंने ये भी अपनी बात में जोड़ा कि औरतें बिज़नेस का नेतृत्व ना भी करती हों तो भी वो खाना तैयार करने की प्रक्रिया में लगी होती हैं। काम करने के बावजूद शिक्षा की कमी, बैंक और पैसों से दूरी की वजह से उनका योगदान नगण्य रह जाता है। ये इस सेक्टर में मौजूद जेंडर खाई को और भी पुख़्ता करता है।

सुरक्षा और सफ़ाई के मुद्दे पर डा॰पटेल ने वाईजेग ट्रेनिंग वर्कशॉप का अपना अनुभव साझा किया जहाँ वेंडरों को पाँच सितारा होटल में साफ़ सफ़ाई के बारे में बताया गया। उपस्थित लोगों से बात करते हुए उन्होंने महसूस किया कि जानकारी के अभाव से ज़्यादा बड़ी समस्या सफ़ाई के लिए ज़रूरी सामान को ख़रीदने की असमर्थता है। मजबूर श्रमिकों और औरतों के इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर संलग्न होने को देखते हुए एक राष्ट्र के तौर पर हमें स्ट्रीट फ़ूड सेक्टर की समस्याओं को सुलझाना या ध्यान देना चाहिए।

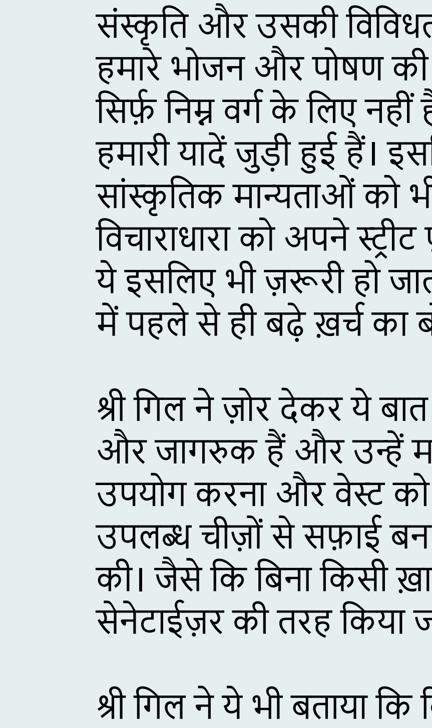

श्री मनजीत गिल

Former Corporate Chef at ITC Hotels I Former President, IFCA

श्री मनजीत गिल, आइ टी सी होटल में कोरपोरेट शेफ़ रह चुके हैं। ये इंडियन फ़ेडेरेशन ओफ़ कुलिनरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। श्री गिल ने इस बात को विशेष रूप से बताया कि स्ट्रीट फ़ूड हमारी संस्कृति और उसकी विविधता को तो दर्शाता ही है और साथ ही साथ हमारे भोजन और पोषण की ज़रूरत को भी पूरा करता है। स्ट्रीट फ़ूड सिर्फ़ निम्न वर्ग के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है क्योंकि इससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए सफ़ाई के मुद्दे की चर्चा के समय हमें सांस्कृतिक मान्यताओं को भी समझना ज़रूरी है।हमें पश्चिमी विचाराधारा को अपने स्ट्रीट फ़ूड वेंडर पर थोपना बंद कर देना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पश्चिमी स्तर को बनाए रखने में पहले से ही बढ़े ख़र्च का बोझ और अधिक हो जाता है।

श्री गिल ने ज़ोर देकर ये बात दोहरायी कि फ़ूड वेंडर काफ़ी शिक्षित और जागरुक हैं और उन्हें मालूम है कि किस तरह से खाने का उपयोग करना और वेस्ट को कम करना है। उन्होंने आसानी से उपलब्ध चीज़ों से सफ़ाई बनाए रखने के रचनात्मक तरीक़ों पर भी बात की। जैसे कि बिना किसी ख़ास ख़र्चे के नींबू के रस का प्रयोग सेनेटाईज़र की तरह किया जा सकता है।

श्री गिल ने ये भी बताया कि किस तरह से दुनिया के कई देशों में वहाँ की सरकारें टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट फ़ूड को प्रोमोट कर रही हैं। कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी स्ट्रीट फ़ूड पर हो रहे हैं। भारत की विविधता से भरी ख़ाने की थाली को दर्शाने वाली क़ाबलियत जो इस सेक्टर में है उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए और बचा कर भी रखना चाहिए।

निष्कर्ष

पूरी चर्चा के दौरान कई नीतिगत सुझाव पेश किए गए। ये केंद्रित थे इंफ़्रास्ट्रकचर सपोर्ट, सरकारी स्कीम और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के इर्द गिर्द हीं। कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं;

- स्ट्रीट वेंडरो को उचित आधारभूत ढाँचा दिया जाना चाहिए। प्रशासन को इन्हें पानी, सफ़ाई, नाली, शौचालय की सुविधा, वेस्ट मेनेजमेंट के उपक्रम, परोसने के लिए पर्यावरण अनुकूल सामान उपलब्ध करवाना चाहिए।
- स्ट्रीट फ़ूड हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रीट फ़ूड वेंडरो पर पश्चिमी स्तर बनाए रखने की ज़रूरत पर दबाव डालना बंद करना चाहिए और किफ़ायती स्थानीय सफ़ाई तरीक़ों को अपनाना चाहिए जो मितव्ययी हों।
- मौजूदा स्कीम और नीतियों के बारे में जागरुकता और जानकारी भी होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी संगठनों और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़रूरतमंद आबादी तक मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का फ़ायदा पहुँच सके।
- आगे बढ़ते हुए, ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर को मौजूद नीतियों के दायरे में लाया जा सके।

स्ट्रीट फ़ूड सेक्टर की बारीकी से स्टडी करने पर पता चलता है कि इस सेक्टर में काफ़ी क्षमता है जिससे कि शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा की तरफ़ ले जाया जा सके। वेबिनार ने फ़ूड सेक्यूरीटी रिसर्च में छिपी कमियों को दूर करने का उद्देश्य निर्धारित किया। इसने कोविड 19 की वजह से स्ट्रीट फ़ूड पर पड़े प्रभाव और उसके आर्थिक पहलू को भी जाँचा। पैनल में शामिल लोगों ने शहरी खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए स्ट्रीट फ़ूड की महत्ता को सामने रखा।

सभी वक्ता जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं उनके विचारों और सुझावों से मौजूदा खाद्य सुरक्षा नीति में व्याप्त छेदों को भरने के लिए किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहली शर्तें हैं, बेहतर इंफ़्रास्ट्रकचर और वेंडर के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ और साथ साथ स्ट्रीट वेंडर को देश के विशाल नीति के दायरे में शामिल करना।

पूरा वीडियो यहां देखें

Social and Political Research Foundation

www.sprf.in

© Social and Political Research Foundation™